

MAINS MATRIX

TABLE OF CONTENT

1. उत्तर-दक्षिण कार्बन बाज़ार सहयोग की शुरुआत
2. चुनाव के मुहाने पर बिहार: सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में सबसे नीचे
3. क्या डोगरी भाषा भारत में अपनी गूंज खो रही है?

उत्तर-दक्षिण कार्बन बाज़ार सहयोग की शुरुआत

संदर्भ और पृष्ठभूमि

घटना की तिथि: 17 सितंबर 2025

मुख्य पक्ष: यूरोपीय संघ (EU) और भारत

अवसर: न्यू स्ट्रैटेजिक ईयू-इंडिया एजेंडा (The New Strategic EU-India Agenda) का शुभारंभ

मुख्य फोकस क्षेत्र (5 स्तंभ):

1. समृद्धि और सततता (Prosperity and Sustainability)
2. प्रौद्योगिकी और नवाचार (Technology and Innovation)
3. सुरक्षा और रक्षा (Security and Defence)
4. संपर्क और वैश्विक मुद्दे (Connectivity and Global Issues)
5. स्वच्छ संक्रमण (Clean Transition)

मुख्य विकास (Core Development)

मुख्य निर्णय:

यूरोपीय संघ भारत के इंडियन कार्बन मार्केट

(ICM) को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से जोड़ेगा।

तंत्र:

भारत में चुकाई गई कार्बन कीमतों ईयू सीमा पर CBAM शुल्क से घटाई जाएँगी।

महत्व (Significance)

- भारतीय निर्यातों पर दोहरी कराधान (CBAM दंड + घरेलू कार्बन लागत) से बचाव संभव।
- न्यायसंगत कार्बन मूल्य निर्धारण और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा।
- जलवायु शासन (climate governance) में उत्तर-दक्षिण सहयोग का ऐतिहासिक उदाहरण।

चुनौतियाँ / अवरोध (Challenges / Barriers)

1. भारत का अपूर्ण विकसित कार्बन बाज़ार

- *Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)* अभी प्रारंभिक और बिखरे स्वरूप में है।

- उत्सर्जन पर कोई पूर्ण सीमा (absolute cap) नहीं — केवल *intensity-based* या *project-level offsets* हैं।
- ईयू के ETS जैसी मजबूत नीलामी संरचना, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया और स्वतंत्र सत्यापन तंत्र का अभाव।

2. नियामकीय और संस्थागत अवरोध

- ईयू के स्वतंत्र नियामकों से जुड़ने की कोई वर्तमान संस्थागत व्यवस्था नहीं।
- ईयू को भारत के कार्बन मूल्यों की पुष्टि हेतु सख्त मानकों की आवश्यकता होगी।
- भारत के लिए ईयू के ETS जैसी संरचना को शीघ्र दोहराना कठिन।

3. मूल्य असमानता (Pricing Gap)

- ईयू ETS कीमतें: €60–€80/टन
- भारत की प्रारंभिक कीमतें: €5–€10/टन
→ जोखिम: ईयू भारत के मूल्य को “अपर्याप्त” मानकर छूट देने से इंकार कर सकता है → व्यापार विवाद।

4. राजनीतिक और संप्रभुता से जुड़ी चिंताएँ

- कार्बन मूल्य निर्धारण घरेलू नीति उपकरण है; इसका जुड़ाव ईयू को भारत

की नीति की “पर्याप्तता” पर अप्रत्यक्ष प्रभाव देता है।

- घरेलू विरोध या अनुपालन में गिरावट से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।

जोखिम और रणनीतिक निहितार्थ (Risks and Strategic Implications)

- यदि भारत का कार्बन मूल्य अपर्याप्त माना गया, तो ईयू पूर्ण CBAM कटौती से इंकार कर सकता है।
- विवाद बढ़कर व्यापार और कूटनीतिक तनाव का रूप ले सकते हैं।
- यह जुड़ाव केवल तकनीकी नहीं — बल्कि WTO कानूनी ढांचे, घरेलू राजनीति और आपसी भरोसे से भी जुड़ा है।

● आशावादी दृष्टिकोण (Optimistic Outlook)

हालाँकि चुनौतियाँ हैं, फिर भी यह जुड़ाव उत्तर-दक्षिण जलवायु सहयोग का एक ऐतिहासिक प्रयास हो सकता है।

संभावित परिणाम:

- भारतीय निर्यात CBAM शुल्क से सुरक्षित होंगे।
- औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहन मिलेगा।

- वैश्विक कार्बन बाज़ार एकीकरण का मॉडल स्थापित हो सकता है।

सफलता के लिए आवश्यक:

- ICM की संरचना और पारदर्शिता को मज़बूत करना।
- नीतिगत विरोधाभासों और भरोसे की कमी को दूर करना।
- संयुक्त संचालन और मानकीकरण तंत्र स्थापित करना।

मुख्य अवधारणाएँ (Key Concepts Mentioned)

अवधारणा	विवरण
ICM (Indian Carbon Market)	भारत का उभरता हुआ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग ढँचा।
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)	ईयू की प्रणाली जो आयात पर कार्बन लागत लगाकर कार्बन लीक को रोकती है।
EU ETS (Emissions Trading System)	ईयू की कार्बन मूल्य निर्धारण और व्यापार प्रणाली, जो वैश्विक मॉडलों की आधारशिला है।

संक्षेप में:

भारत-ईयू कार्बन बाज़ार जुड़ाव केवल व्यापारिक पहल नहीं है — यह जलवायु नीति में उत्तर-दक्षिण सहयोग का नया अध्याय है। यदि इसे पारदर्शी और न्यायसंगत ढंग से लागू किया गया, तो यह वैश्विक क्लाइमेट जस्टिस की दिशा में एक मील का पत्थर सिट्थ हो सकता है।

HOW TO USE IT

प्रस्तावित भारतीय कार्बन मार्केट (ICM) और यूरोपीय संघ के कार्बन बोर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के बीच जुड़ाव (linkage) वैश्विक जलवायु शासन में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है।

यह उत्तर-दक्षिण सहयोग (North-South cooperation) का एक उच्च जोखिम वाला प्रयोग है — जो या तो भारतीय उद्योगों को संरक्षण देकर डिकार्बोनाइजेशन को गति दे सकता है, या फिर व्यापार विवादों को जन्म दे सकता है, जिससे जलवायु कार्रवाई, आर्थिक संप्रभुता, और निष्पक्ष व्यापार के बीच तनाव उजागर होता है।

◆ प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा)

1. संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और हास, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

कैसे उपयोग करें:

यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बाजार-

आधारित (market-based) तंत्रों का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है।

मुख्य बिंदु:

- **कार्बन प्राइसिंग** एक उपकरण के रूप में: कार्बन बाज़ार प्रदूषण पर “मूल्य लगाने” का कार्य करते हैं — जिससे उद्योगों को उत्सर्जन घटाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यूरोपीय संघ की *Emissions Trading Scheme (ETS)* दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी प्रणाली है।
- **डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना:** यह जुड़ाव भारतीय निर्यातकों को अपने कार्बन फुटप्रिंट घटाने का सीधा आर्थिक प्रोत्साहन देता है। कम कार्बन तीव्रता (carbon intensity) = कम CBAM शुल्क → वस्तुएँ अधिक प्रतिस्पर्धी।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था — योजना, संसाधनों की जुटान, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

कैसे उपयोग करें:

इसका भारतीय औद्योगिक नीति और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर गहरा प्रभाव है।

मुख्य बिंदु:

- **CBAM से निर्यात की सुरक्षा:** यह जुड़ाव भारतीय निर्यातों (जैसे — स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट) को यूरोपीय संघ के **CBAM टैक्स** से बचाता है। इसके बिना, भारतीय वस्तुएँ महँगी पड़तीं और प्रतिस्पर्धात्मकता घट जाती। यह “दोहरी कराधान (double taxation)” को रोकता है।
- **“ग्रीन प्रीमियम” की अवधारणा:** कम-कार्बन उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को “ग्रीन प्रीमियम” मिलेगा, जिससे आर्थिक वृद्धि और जलवायु लक्ष्यों (पंचामृत) के बीच तालमेल बनेगा।
- **नवजात बाज़ार की चुनौती:** *EU ETS* — परिपक्व, सशक्त प्रणाली (absolute caps, €60–€80/टन)। **भारत का CCTS** — प्रारंभिक अवस्था, intensity-based, कम मूल्य (€5–€10/टन)। यही मूल्य अंतर (price gap) सबसे बड़ी बाधा है।

◆ द्वितीयक प्रासंगिकता: GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

1. भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समझौते

कैसे उपयोग करें:

यह एक प्रमुख द्विपक्षीय पहल है, जिसका वैशिक प्रभाव हो सकता है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर-दक्षिण सहयोग का मॉडल:**
यदि सफल रहा, तो यह विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग का नया टेम्पलेट बन सकता है, जो पारंपरिक “जिम्मेदारी के आरोप-प्रत्यारोप” से आगे बढ़ेगा।
- संप्रभुता की चिंता (Sovereignty Concerns):**
यह जुड़ाव ईयू को भारत के कार्बन मूल्य की “पर्याप्तता” पर राय देने का अवसर देता है।
यह नीति-निर्धारण में भारत की संप्रभुता (policy sovereignty) से जुड़ा संवेदनशील प्रश्न है।
- WTO अनुकूलता (WTO Compatibility):**
इस समझौते को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अनुरूप रहना होगा ताकि यह भेदभावपूर्ण व्यापार अवरोध (discriminatory trade barrier) के रूप में न देखा जाए।

संक्षेप में:

ICM-CBAM जुड़ाव केवल पर्यावरणीय तंत्र नहीं, बल्कि यह आर्थिक नीति, वैशिक व्यापार व्यवस्था और जलवायु न्याय के संगम पर स्थित एक रणनीतिक पहल है।
इसकी सफलता भारत की जलवायु कूटनीति और हरित औद्योगिक परिवर्तन (green industrial transition) की दिशा तय कर सकती है।

चुनाव के मुहाने पर बिहार: सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में सबसे नीचे

⌚ प्रसंग और पृष्ठभूमि

घटना: बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को होने वाले हैं।

मुख्य खिलाड़ी: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बनाम महागठबंधन (Grand Alliance)।

केन्द्र: चुनाव पूर्व बिहार के सामाजिक और आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण।

डेटा स्रोत:

- नीति आयोग (NITI Aayog)
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI)
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

📊 समग्र निष्कर्ष

बिहार मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संकेतकों में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में बना हुआ है।

मानव विकास सूचकांक (HDI) 2022 में बिहार अंतिम (27वां) स्थान पर रहा — HDI स्कोर 0.609, जबकि शीर्ष राज्य केरल का स्कोर 0.789 था।

 1. स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतक (2019-21)

संकेतक	बिहार का मान	बिहार की रैंक	शीर्ष राज्य का मान
15+ वर्ष की महिलाओं में जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई की (%)	61.1	28/29	केरल 98.5
20-24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह (%)	40.8	सबसे अधिक (सबसे खराब)	-

संकेतक	बिहार का मान	बिहार की रैंक	शीर्ष राज्य का मान
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	46.8	21/27	केरल 5.4
5 वर्ष से कम आयु के अवरुद्ध (Stunted) बच्चे (%)	42.9	22/27	तमिलनाडु 23.1
5 वर्ष से कम आयु के क्षीण (Wasted) बच्चे (%)	22.9	21/27	केरल 10.8
5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चे (%)	29.0	24/27	पंजाब 16.9
बेहतर स्वच्छता	49.4	26.5/27	केरल 98.5

संकेतक	बिहार का मान	बिहार की रैंक	शीर्ष राज्य का रैंक	शीर्ष राज्य का मान
सुविधाओं वाले घर (%)				

◆ व्याख्या:

महिलाओं की शिक्षा, बाल स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में बिहार काफी पीछे है, हालाँकि 2005–06 और 2015–16 की तुलना में मामूली सुधार देखा गया है।

2. मानव विकास सूचकांक (HDI)

संकेतक	मान (2022)	बिहार की रैंक	शीर्ष राज्य	शीर्ष राज्य का मान
HDI	0.609	27/27	केरल	0.789

◆ निष्कर्ष: बिहार का HDI देश में सबसे कम है।

3. आर्थिक प्रदर्शन (प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद - NSDP)

संकेतक	मान (₹, चालू मूल्य 2023-24)	बिहार की रैंक	शीर्ष राज्य	शीर्ष राज्य का मान
प्रति व्यक्ति NSDP	₹ 60,337	25/25	तेलंगाना	₹ 3,56,564

◆ निष्कर्ष: बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है — तेलंगाना की तुलना में लगभग 1/6वां भाग।

4. रोजगार संरचना

क्षेत्र	भागीदारी (2023-24)	बिहार की रैंक	शीर्ष राज्य	शीर्ष राज्य का मान
सेवा क्षेत्र में	25.5%	28/29	केरल	44.2%
विनिर्माण क्षेत्र में	5.7%	29/29	महाराष्ट्र	38.1%

◆ निष्कर्ष: बिहार की अर्थव्यवस्था अब भी अत्यधिक कृषि-आधारित (agrarian) है, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत कम है।

5. शिक्षा संकेतक (2023-24)

संकेतक	मान	बिहार की रँक	शीर्ष राज्य का मान	शीर्ष राज्य का मान
शुद्ध नामांकन (कक्षा 1-5)	97.2%	19/29	कई राज्य	99%+
ड्रॉपआउट दर (कक्षा 1-10)	19.5%	24/29	हिमाचल प्रदेश	1.9%
सकल नामांकन अनुपात (कक्षा 11-12)	48.4%	27/29	केरल	85.6%
उच्च शिक्षा में सकल नामांकन (18-23 वर्ष)	17.1%	28/29	तमिलनाडु	47.9%

◆ निष्कर्ष: बिहार में उच्च ड्रॉपआउट दर और उच्च शिक्षा में अत्यंत कम नामांकन चिंता का विषय है।

6. पर्यावरणीय संकेतक (2023-24)

संकेतक	मान	बिहार की रँक	शीर्ष राज्य का मान	शीर्ष राज्य का मान
प्लास्टिक कचरा उत्पादन (किग्रा/व्यक्ति)	0.61	1	1/29 (सर्वश्रेष्ठ)	झारखण्ड 0.63
वार्षिक प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन खपत (GJ)	44.7	44.	1/29 (सर्वश्रेष्ठ)	असम 88.4

◆ व्याख्या:

पर्यावरणीय प्रदर्शन बेहतर दिखता है, परंतु इसका कारण कम औद्योगिकीकरण और ऊर्जा खपत है, न कि वास्तविक पर्यावरणीय दक्षता (environmental efficiency)।

सारांश:

बिहार मानव विकास और आर्थिक प्रगति के लगभग सभी क्षेत्रों में देश के सबसे निचले स्तर पर है।

आगामी चुनावों में यह स्थिति नीतिगत बहस का प्रमुख मुद्दा बन सकती है —

क्या राज्य विकास के “न्यूनतम मानक” तक पहुँच पाएगा या नहीं, यही असली सवाल है।

HOW TO USE IT

यह आँकड़ा “अविकास”, “क्षेत्रीय असमानता” और “शासन विफलता” जैसे अमूर्त अवधारणाओं को ठोस, मापने योग्य तथ्यों में बदल देता है। इससे आप सामान्य बयानों से आगे बढ़कर साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं — जो उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर। (भारतीय समाज)

1. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता:

कैसे उपयोग करें:

यह डेटा भारत के विभिन्न राज्यों में विकास के परिणामों की तीव्र विविधता को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु:

- बिहार (HDI: 0.609) और केरल (HDI: 0.789) के बीच तुलना का उपयोग उत्तर-दक्षिण विभाजन और एक ही राष्ट्र के भीतर सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों को समझाने के लिए किया जा सकता है।
- बाल विवाह (40.8%) और महिला शिक्षा (61.1% ने कभी स्कूल में पढ़ाई की) से संबंधित आँकड़े पिरूसतात्मक

सामाजिक संरचनाओं और उनके पीढ़ीगत प्रभावों पर चर्चा करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रदान करते हैं।

2. महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन:

कैसे उपयोग करें:

महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित आँकड़े इस विषय के केंद्र में हैं।

मुख्य बिंदु:

- बाल विवाह की उच्च दर सीधे उच्च शिशु मृत्यु दर (46.8) और अवरुद्ध (stunted) बच्चों (42.9%) तथा कम वजन वाले बच्चों (29.0%) की दरों से जुड़ी है।
- यह आँकड़े दिखाते हैं कि कैसे लैंगिक भेदभाव और स्वास्थ्य परिणामों के बीच एक चक्रीय संबंध (cyclical relationship) बना रहता है।

3. गरीबी और विकास से जुड़ी समस्याएँ:

कैसे उपयोग करें:

यह बहुआयामी गरीबी (multidimensional poverty) का प्रत्यक्ष केस स्टडी है।

मुख्य बिंदु:

- बिहार का प्रति व्यक्ति NSDP (₹60,337) में अंतिम स्थान आय-आधारित गरीबी का पारंपरिक संकेतक है।

- लेकिन स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा से जुड़े आँकड़े दिखाते हैं कि समस्या केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है — यह एक बहुआयामी विकास संकट है।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर ॥ (शासन, सामाजिक न्याय)

1. गरीबी और भूख से जुड़ी समस्याएँ:

कैसे उपयोग करें:

स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े आँकड़े यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

- बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की उच्च दरें लंबे समय से चली आ रही भूख और कुपोषण की स्थिति का संकेत देती हैं — जबकि केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएँ लागू की जा चुकी हैं।

2. कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ:

कैसे उपयोग करें:

यह आँकड़ा पिछले दशकों की योजनाओं की प्रभावशीलता पर रिपोर्ट कार्ड की तरह कार्य करता है।

मुख्य बिंदु:

- अनेक योजनाओं (जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत

मिशन) के बावजूद बिहार के परिणाम सबसे खराब हैं।

- यह नीति के उद्देश्य और कार्यान्वयन के बीच अंतर (implementation gap) को उजागर करता है, जो कमज़ोर शासन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी से जुड़ा है।

3. विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग — एनजीओ, एसएचजी आदि की भूमिका:

कैसे उपयोग करें:

यह आँकड़ा नागरिक समाज के हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य की असफलता यह दर्शाती है कि महिलाओं की साक्षरता, स्वच्छता जागरूकता और स्वास्थ्य पहुँच जैसे क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और NGOs की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर ॥ (अर्थव्यवस्था, कृषि)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन से जुड़ी समस्याएँ:

कैसे उपयोग करें:

आर्थिक संरचना से संबंधित डेटा यहाँ महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु:

- बिहार की अर्थव्यवस्था निम्न-विकास जाल (low-growth trap) में फँसी हुई है।
- केवल 5.7% विनिर्माण (manufacturing) और 25.5% सेवा क्षेत्र में होने से यह अब भी कृषि पर निर्भर है और औद्योगिकीकरण व आधुनिक सेवा क्षेत्र के अवसरों से वंचित रह गया है।

2. रोजगार:

कैसे उपयोग करें:

क्षेत्रवार रोजगार का डेटा प्रवासन और बेरोजगारी की व्याख्या करता है।

मुख्य बिंदु:

- औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में रोजगार की कमी (जो भारत में सबसे कम है) बिहार से अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रवासन का मुख्य कारण है — जिसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव गहरे हैं।

3. खाद्य सुरक्षा:

कैसे उपयोग करें:

बाल कुपोषण से जुड़े आँकड़े सीधे खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं।

मुख्य बिंदु:

- तर्क तैं कि खाद्य सुरक्षा केवल उपलब्धता (PDS) तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पहुँच, वहनीयता और पोषण गुणवत्ता भी शामिल हैं — जो बिहार में गंभीर रूप से कमी में हैं।

क्या डोगरी भाषा भारत में अपनी गूंज खो रही है?

संदर्भ और पृष्ठभूमि

वैशिक चिंता:

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे अधिक बोलियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं — पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएँ गायब हो चुकी हैं।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य:

जम्मू क्षेत्र में डोगरी भाषा के धीरे-धीरे पतन को लेकर चिंता बढ़ रही है।

व्यापक मुद्दा:

वैश्वीकरण, प्रवास और आर्थिक प्राथमिकताएँ वक्ताओं को अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषाओं (उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी) की ओर प्रेरित कर रही हैं, जिससे डोगरी हाशिए पर चली जा रही है।

क्या डोगरी भाषा पतन की ओर है?

पतन के कारण:

1. सरकारी नीतिगत अंतर

- यद्यपि 2020 के जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषाएँ विधेयक में डोगरी को संघ शासित प्रदेश की पाँच आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन बहुत सीमित रहा है।
- शिक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र में डोगरी की दृश्यता और संस्थागत समर्थन का अभाव है।

2. पीढ़ीगत दृष्टिकोण

- युवा पीढ़ी में डोगरी पढ़ने-लिखने और बोलने की क्षमता में भारी गिरावट देखी गई है।
- बुजुर्ग (60+) वर्ग में बोलने और पढ़ने की पूरी दक्षता है, लेकिन 41-60 आयु वर्ग में यह घटकर बहुत कम रह गई है और 20 वर्ष से कम आयु के लोगों में लगभग अनुपस्थित है।

3. ग्रामीण-शहरी विभाजन

- ग्रामीण उत्तरदाता: 56% डोगरी बोलते हैं; लगभग 15% लिख सकते हैं।
- शहरी उत्तरदाता: केवल 45% बोलते हैं; लगभग 4% लिख सकते हैं।
- यह प्रवास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और शहरी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी/हिंदी की प्राथमिकता को दर्शाता है।

सर्वेक्षण निष्कर्ष

नमूना: जम्मू क्षेत्र के 200 प्रतिभागी (130 पूर्ण उत्तर)।

विधि: यादृच्छिक नमूना।

मुख्य डेटा:

- 48% का मानना है कि सरकार ने डोगरी को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं दिया।
- 32% को लगता है कि डोगरी में रोजगार के अवसर सीमित हैं।
- 25% ने मध्यम सरकारी समर्थन महसूस किया।

पीढ़ीगत दक्षता में गिरावट

आयु समूह	बोलने की दक्षता	पढ़ने/लिखने की दक्षता
60+ वर्ष	पूर्ण दक्षता	मध्यम स्तर
41-60 वर्ष	मध्यम	0.25% साक्षरता
20 वर्ष से कम	0% साक्षरता	0% पढ़ने/लिखने की दक्षता

→ यह भाषाई हस्तांतरण में गंभीर पीढ़ीगत क्षरण को दर्शाता है।

ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक

- डोगरी को 2003 में संवैधानिक मान्यता मिली — अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में बहुत देर से।

- तब तक भाषा संस्थागत रूप से पिछड़ चुकी थी।
- उर्दू और कश्मीरी के विपरीत, डोगरी शिक्षा और प्रशासन से लगभग अनुपस्थित रही।

मुख्य विश्लेषण

आयाम	अंतर्दृष्टि
सांस्कृतिक	युवा पीढ़ी में पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता का ह्रास।
राजनीतिक	मान्यता तो मिली, पर नीतिगत क्रियान्वयन और संस्थागत समर्थन का अभाव।
आर्थिक	रोजगार और गतिशीलता के लिए अंग्रेज़ी/हिंदी को प्राथमिकता।
समाजशास्त्रीय	ग्रामीण क्षेत्रों में भाषाई लगाव कायम, शहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक अलगाव।

आगे की राह

1. तकनीकी उपाय

- लुप्तप्राय भाषाओं पर अद्यतन जनगणना डेटा आवश्यक।

- भाषा-निगरानी और पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।

2. नीतिगत उपाय

- स्कूल पाठ्यक्रम, सार्वजनिक संकेतों, मीडिया और प्रशासन में डोगरी को बढ़ावा दिया जाए।
- द्विभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन ताकि पीढ़ियों में भाषा का स्थानांतरण बना रहे।
- समुदाय-आधारित संरक्षण पहल को समर्थन।

3. सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का प्रतिरोध

- “अंग्रेज़ी = प्रगति” की मानसिकता को चुनौती।
- सांस्कृतिक उत्सवों और डिजिटल माध्यमों से भाषाई विविधता पर गर्व का प्रचार।

सारांश (THE GIST)

प्रमुख बिंदु	सारांश
वैश्वीकरण और प्रवास	व्यापक भाषाओं को अपनाने की प्रवृत्ति से डोगरी जैसी भाषाएँ मिटती जा रही हैं।
अध्ययन के तीन दृष्टिकोण	सरकारी नीति, पीढ़ीगत दृष्टिकोण, ग्रामीण-शहरी विभाजन।

प्रमुख बिंदु	सारांश
सर्वेक्षण निष्कर्ष	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट अंतर; बुजुर्ग दक्ष, युवा विमुख।

HOW TO USE IT

डोगरी भाषा का पतन केवल एक भाषाई समस्या नहीं है, बल्कि यह वैश्वीकरण, राज्य नीति, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक मान्यता के जटिल अंतःक्रिया (interplay) का लक्षण है। यह उप-क्षेत्रीय संस्कृतियों के उस संघर्ष का प्रतीक है जो एक समानता-उन्मुख (homogenizing) विश्व में अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। यह संवैधानिक मान्यता और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की खाई को भी उजागर करता है।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर। (भारतीय समाज)

1. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता:

कैसे उपयोग करें:

यह विषय सबसे प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त है। भारत की विविधता उसकी शक्ति है, और डोगरी जैसी भाषाओं का क्षरण इस बहुलतावादी तानेबाने को सीधे चुनौती देता है।

मुख्य बिंदु:

- इस आँकड़े का उपयोग यह तर्क देने के लिए करें कि भारत की “विविधता में एकता” दबाव में है। पीढ़ीगत गिरावट (60 वर्ष से ऊपर वालों में पूर्ण दक्षता बनाम 20 वर्ष से कम वालों में 0% साक्षरता) सांस्कृतिक पूँजी के तीव्र हास को दर्शाती है।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन (ग्रामीण क्षेत्रों में 56% बनाम शहरी में 45% वक्ता) दिखाता है कि आधुनिकीकरण और प्रवासन इस सांस्कृतिक समानता (homogenization) को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं।

2. भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव:

कैसे उपयोग करें:

लेख में वैश्वीकरण को सीधे तौर पर डोगरी के पतन का कारण बताया गया है।

मुख्य बिंदु:

- आर्थिक गतिशीलता के लिए अंग्रेजी और हिंदी को प्राथमिकता देना वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, 32% लोगों का मानना है कि डोगरी से रोजगार के अवसर सीमित हैं — यह तथ्य यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर। (शासन, संविधान)

1. भारतीय संविधान — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएँ:

कैसे उपयोग करें:

यह मुद्रा मौलिक अधिकारों और आधिकारिक भाषा नीति से जुड़ा है।

मुख्य बिंदु:

- संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) का उल्लेख करें — डोगरी को 2003 में शामिल किया गया था, जो एक सकारात्मक कदम था, लेकिन यह मामला दिखाता है कि केवल शामिल कर लेने से संरक्षण सुनिश्चित नहीं होता जब तक सरकार सक्रिय रूप से प्रोत्साहन न दे।
- इसे अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण) से जोड़ें — जो भाषाई अल्पसंख्यकों पर भी लागू किया जा सकता है।

2. विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप:

कैसे उपयोग करें:

यह नीति और क्रियान्वयन (implementation) के बीच के अंतर का एक स्पष्ट उदाहरण है।

मुख्य बिंदु:

- जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम, 2020 के तहत डोगरी को

आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, लेकिन सर्वेक्षण में 48% लोगों ने माना कि सरकार इसे बढ़ावा देने में विफल रही।

- यह एक “नीति-उद्देश्य बनाम कार्यान्वयन” की क्लासिक विफलता है — विशेषकर शिक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक संकेतों (signage) में कमी के कारण।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर IV (नीति-नैतिकता)

1. दृष्टिकोण (Attitude): इसकी सामग्री, संरचना, कार्य और विचार व व्यवहार पर प्रभाव:

कैसे उपयोग करें:

भाषा का पतन समाज के दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा है।

मुख्य बिंदु:

- “सांस्कृतिक उपनिवेशवाद से मुक्ति” (Cultural Decolonisation) की आवश्यकता इस बात को दर्शाती है कि यह केवल भाषाई नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण की समस्या है — जहाँ अंग्रेजी को “प्रगति” और क्षेत्रीय भाषाओं को “पिछ़ापन” माना जाता है।
- इस दृष्टिकोण को बदलना ही भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण की कुंजी है।

DAILY ANSWER WRITING



OPTIONAL (PSIR , SOCIOLOGY ,
ANTHROPOLOGY)

TACKLE MOST
PROBABLE
QUESTIONS

EVALUATION
WITHIN 24-36
HOUR

Learn with
Quality Model
Answers

WRITE DAILY. IMPROVE DAILY. ACHIEVE EXCELLENCE

MOST AFFORDABLE

BATCH STARTS : 1 NOVEMBER

CONTACT - 7509519261 | WWW.MENTORAIAS.CO.IN

★ DAILY ANSWER WRITING (DAW) PROGRAM ★ -

► Register Now: www.mentoraias.co.in/test-series

MENTORA IAS

“YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT”